पास के करीब तीस लाख लोग यहां की बसों का इस्तेमाल करते हैं । इस हिसाब से बसों की प्राप्त करने की संख्या नाकाफी है ।

दूसरे मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि जिन घनी आबादी वाले इलाकों में बसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है उनमें उतनी बसें क्या नहीं चलायी जा रही है, जितनी की आवश्यकता है और जिन इलाकों में बसों की उतनी आवश्यकता नहीं है वहां भी उसी अनुपात में बसें चलायी हैं जितनी कि घनी आबादी वाले इलाकों में चलायी जाती हैं ।

श्री चांद राम : श्रीमन्, इस सारे मामले की जांच करने के लिये मैंने एक इंक्वायरी कमेटी कंस्टीट्यूट की है । वह पूरे नान-आफिशियल-की कमेटी है, उसमें कई इंटरेस्ट रिप्रजन्टेड हैं । वह कमेटी इस बात को भी देख रही है कि जहां-जहां कंजेस्शन है वह कंजेस्शन दूर किया जाए । उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और जैसा कि मैंने कहा हम और बसें जोड़ रहे हैं, उससे स्थिति में सुधार हो जाएगा ।

SHRI GIAN CHAND TOTU: What are the terms on which private buses are attached to DTC.

श्री चांद राम : दो प्रकार की टर्म हैं । एक टर्म यह है कि कुछ बसें किलोमीटर की स्कीम पर हैं जैसे कोई बस 250 किलो मीटर तक रन करेंगी तो इतना पैसा मिलेगा और जो बसें पुरानी है उनके लिए दो हजार किलो-मीटर रखा है उनको दूसरे हिसाब से पैसा मिलेगा और जो चार साल पुरानी है उनके लिये दूसरे हिसाब से पैसा देना पड़ेगा । दूसरी टर्म यह है कि कुछ बसों को हजार रुपया देकर चलवाते है । ये बसें डी० टी० सी० आपरेशन के मातहत ही चलती है ।

SHRI SYED NIZAM-UD-DIN: I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that students are put to much difficulty in Delhi during peak hours? If so, will he consider the proposal that certain buses are allocated to schools, so that these boys and girls going to schools are not put to any difficulty and they reach their schools in time? Accidents take place because boys run after buses and try to catch them in any way they can do it. Therefore, if an exclusive allotment is done of buses for school children, this would help children from far off places like Janakpuri and others.

SHRI CHAND RAM: So far as students' difficulties are concerned, I have already taken certain steps. We have included students' representatives not only in the advisory body but also in the DTC Enquiry Committee, and I can assure hon. Members that so far as students are concerned they are perfectly satisfied, and if there are any more problems for students, these will be looked into sympathetically.

SHRI U. R. KRISHNAN: May I know from the hon. Minister whether during peak hours some more buses will be introduced on certain important routs?

SHRI CHAND RAM: We shall consider this. If more buses are required, certainly we will do it.

Textile mills under the control of N.T.C.

*489. SHRI U. R. KRISHNAN: Will the Minister or INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the number of textile mills under the control of the National Textiles Corporation Statewise; and

(b) what is the number of textile mills, out of them, which are earning profit?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) There are 105 textile mills under the National Textile Corporation at present The State-wise distribution of these mills is as under:—

	Name of the State/Union Territory	No. of mills
1.	Andhra Pradesh	6
2.	Assam	1
3.	Bihar	2
4.	Gujarat	12
5.	Karnataka	4
6.	Kerala	5
7.	Madhya Pradesh	7
8.	Maharashtra	22
9.	Orissa	1
10.	Punjab	4
11.	Rajasthan	3
12.	Tamil Nadu	14
13.	Uttar Pradesh	7
14.	West Bengal	14
15.	Delhi	1
16.	Pondicherry	2

(b) In the month of January, 1978, 45 mills showed profit. Of these, 23 mills earned cumulative profit during the period April, 1977 to January, 1978.

SHRI U. R. KRISHNAN: Sir, from the statement laid on the Table, it is clear that the cotton textile industry in our country is facing a grave situation due to lack of finance, obsolete machinery and the problem of high cost of production of cloth. In this connection, will the Government come forward to take over the sick units under the N.T.C.?

SHRI GEORGE FERNANDES: There is no proposal just now to take over any more units.

SHRI U. R. KRISHNAN: More than sixty cotton industrial units are running at a loss under the N.T.C. What are the main reasons for this, and what are the steps proposed to be taken in this regard?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, the N.T.C. took over sick mills in other words, when they were running at a loss and others that had closed down because of losses. These losses were due to a variety of reasons. Mismanagement was there But since the N.T.C. has taken over things have improved. But one need not hold a brief for just everybody There can be occasions and situations where things are not properly managed. Then, Sir, there is the question of obsolete machinery that is there in some of these mills. We are trying to modernise this machinery and thus do away with one of the causes of these losses. Thirdly, there is excessive labour also, because over the years these units were not properly managed. The machinery became obsolete and it had to be condemned but the workers stayed on. And they had to pay to the workers who did not necessarily have any gainful employment in these mills. Then, Sir, there have been problems of marketing. There have been problems of diversification of the kind of cloth needed to be produced. So a variety of reasons have contributed to the loss incurred by some of the NTC units. However, Sir, I am very pleased to inform hon. Members that while in December 1976 only 18 mills made profits, in December 1977, that is, over a period of twelve months, due to the efforts made by the N.T.C., 15 mills have started making profits. We hope to improve the situation in the coming months.

SHRI S. W. DHABE: May I know from the hon. Minister this things? He has rightly said that 45 mills have started making profits due to the industrial peace maintained by the working class and also due to the efforts of the hon. Minister who is the champion of the working class. May

I know from the hon. Minister whether there is any proposal to close or scrap some of the N.T.C. mills which are making continuous losses. There is such a fear in Maharashtra and other places. If there is such a proposal, is there another proposal also for providing, alternative employment to the workers?

SHRI GEORGE FERNANDES: I have no proposal under consideration for scraping any unit. We are seriously trying to see how the N.T.C. could be better managed and whether some form of decentralisation could also be brought about in respect of some of them. This will be done in consultation with the workers and their units.

श्री रामानन्द यादव : सभापति जी, माननीय मंत्री जी जानते हैं कि लगभग 60 मिल ऐसी हैं जो कि टेक्सटाइल कारपोरेशन के अन्तर्गत हैं और वे लौस में चल रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन मिलों को लाभप्रदरूप से चलाने के लिए सरकार के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और कारपोरेशन ने इस काम के लिए कितनी पूंजी आवंटित की है ताकि इन मिलों को लाभप्रद रूप से चलाया जा सके ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सभापति जी, इन मिलों में जिस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है वह एक लम्बी प्रक्रिया है और मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया है। पहली बात तो यह है कि जो पुरानी मशीनरी है उसको सुधारने के लिए और उसके स्थान पर नई मशीनरी प्राप्त करने के लिए काम चल रहा है। इस काम में तीन, चार, या पांच वर्ष लग सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी यह नीति है कि जिन मिलों में 10 फीसदी या 12 फीसदी मजदूर ज्यादा है उनको मिलों से निकाला नहीं जाय बल्कि उनको दूसरे उपयोगी कार्यों में लगाया जाय। इस वक्त एन० टी० सी० में डेढ़ लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें से 10 या 12 फीसदी कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हैं। हम इनको निकाल नहीं रहे हैं। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और कोई अन्य तौर तरीका निकालने का प्रयास कर रहे हैं जिसके चलते उन लोगों को कोई दूसरा काम मिल सके। एक तरीका यह भी सोचा गया है कि पावरलूम के काम में उन लोगों को लगाया जाय। ये सारे प्रयास हमारी तरफ से चल रहे हैं। इसके साथ इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि जो कपास खरीदने का तरीका है या जो कपास खरीदने का सिलसिला है उसमें कोई सुधार लाया जाय। इस संबंध में काटन कारपोरेशन एन० टी० सी० और सरकार की बातचीत चल रही है और यह सोचा जा रहा है कि बाजार में काटन के दामों में जो चढ़ाव आता है उसका गलत असर इस पर न हो। जहां तक मार्किट का सवाल है, यह कहा जाता है कि एन० टी० सी० की बाजार में दुकान नहीं हैं। इस बारे मे भी विचार किया जा रहा है। खासतौर पर हमारे देश में जो पिछड़े इलाके हैं, जहां पर एन० टी० सी० का कपड़ा अधिक मात्रा में इस्तमाल किया जाता है, उन इलाकों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाय। आखिरी बात यह है कि हमारे देश के अन्दर जो मजदूर संघ हैं, उनके प्रतिनिधियों की तथा अन्य लोगों की हमने एक कमटी बनाई है। वह कमटी एन० टी० सी० में सुधार के बारे में और उसकी मिलों में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, इस बारे में अपनी रपट देगी। उसकी रपट आने के बाद इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री हर्षदेव मालवीय : मान्यवर, मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने काटन कारपोरेशन की बात कहीं। उनको इस बात की जानकारी होगी कि पब्लिक अन्डर टर्किग्स कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट में यह कहा था कि काटन कारपोरेशन और टैक्सटाइल कारपोरेशन, दोनों सरकारी मशीनरीज हैं, इसलिए इन दोनों को मिला दिया जाय ताकि काटन के खरीदने में जो दिक्कत होती हैं

उनको समाप्त किया जा सके । अभी यह स्थिति है कि काटन खरीदने के मामले में काटन कारपोरेशन आफ इंडिया किसानों को बेवकूफ बनाता रहता है । इसीलिए पब्लिक अन्डर टेकिंग्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि इन दोनों को मिला दिया जाये । यह भी आप जानते हैं कि काटन कारपोरेशन के बारे में सी० बी० आई० की इन्क्वायरी चल रही है । ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि काटन कारपोरेशन और नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन को मिला दिया जाये और क्या इस तरफ सरकार ने कोई ध्यान दिया है ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सभापति जी, हमारे सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं है और न ही हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं । नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन और काटन कारपोरेशन दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं और इन दोनों का काम अलग अलग चलता है । काटन खरीदने के काम में हम जरूर सुधार लाना चाहते हैं । अगर कोई कोआपरेटिव सोसायटी या राज्य सरकारें इस संबंध में दिलचस्पी लेना चाहें तो हम उनका भी सहयोग लेंगे । जहां तक दोनों को मिलाने का सवाल है, इस प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं करते हैं ।

SHRI G. LAKSHMANAN: Sir, these sick mills have become sick to the nation and we find that after working for some time, all these mills become sick as any person becomes sick after some time. Therefore, I would like to ask the hon. Minister for Industries, with all his progressive views, as to what is the policy of the Government. When a mill is sick, he exploits the people.

SHRI GEORGE FERNANDES: Who?

SHRI G. LAKSHMANAN: Not Mr. Fernandes. And the capitalist says that the mill is sick. Then the Government intervenes and starts the National Textile Corporation. I would like to ask the hon. Minister as to what the policy of the Government is with regard to nationalisation of textile industry in this country.

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, we have just now no proposal to nationalise the textile industry. As the hon. Member knows, under the new 'Industrial Policy, we are trying to decentralise the textile sector to the extent possible. We have decided that there shall be no additional loomage in the organised textile sector or in the powerloom sector, and that the additional loomage shall be in the handloom sector. This is the decision that has been taken and that is being implemented. Sir, the hon. Member is right in his criticism of the private mill-owners. There is justification in whatever the hon. Member has said. But this is a problem that will take some time for us to resolve.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: Sir, some of the yarn units are composite units. Most of the sick and closed units are yarn units located in South India in the Coimbatore area and some in Gujarat and in Bombay also. But mostly they are non-composite units and yarn units. But some of the composite units located elsewhere and which have to be fed by these yarn units are short of yarn, and because of the transport costs, they find it uneconomic to have their intermediary raw materials, that is yarn, from a long distance. In view of this would the hon. Minister be kind enough to consider setting up of some yarn units having primarily in view the needs of the weavers because he is emphasising and I think rightly so the increasing role of the decentralised weaver sectors? Sir, they are often starved of yarn and it has to be brought in from a long distance. Sir, there was at one stage an idea to have large-sized and not small-sized yarn mills because the question of economics of the scale will be coming. Sir, though we want

to serve the weaver sector, the hon. Minister must be aware that the weaver sector particularly had to be subsidized to make the cloth available at a reasonable price to the people. Therefore, I would like to know whether the setting up of this sort of large-sized yarn mills, preferably in areas where the weavers concentration is higher, is under the consideration of the Government.

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, I shall give the utmost consideration to the suggestions made by the hon. Member.

श्री जगदीश जोशी : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम है कि बहुत सी सिक मिलें मशीनों के खराब होने की वजह से भी बीमार पड़ गई थीं। तो उनके आधुनिकीकरण के लिये और मजदूरों का सहयोग बढ़ाने के लिये, मजदूरों को काम चलाने में साझेदारी देने के लिये, ट्रस्टीशिप के आधार पर क्या कोई योजना मंत्री जी के दिमाग में है, ताकि वे सारे कारखाने जो एन० टी० सी० में हैं, वे गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के आधार पर मजदूर और सरकार के सहयोग से चले। क्या मंत्री महोदय मजदूरों की भी उनके मालिकाना हक देने के बारे में कोई विचार कर रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सभापति जी, यह बात सही है कि मशीनरी पुरानी थी और बुरी मशीनरी के चलते यह स्थिति बिगड़ी है। एन० टी० सी० ने अपनी मिलों को सुधारने के लिये जो योजना बनाई है, उसमें दो सौ करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने का इन्तजाम है और अन्दाजन 60 करोड़ रुपये की नई मशीनरी ला कर काम शुरू हो चुका है। जहां तक मजदूरों की साझेदारी और मजदूरों को मिलों को चलाने के काम से जोड़ने की बात है, सभापति जी, मैंने पहले ही कहा था कि . . .

श्री जगदीश जोशी : और ट्रस्टीशिप के बारे में क्या विचार है।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सारी चीजें इसी में आ जायेंगी, चाहे आप पार्टनरशिप कहें या ट्रस्टीशिप कहें।

सभापति जी, मैंने पहले ही कहा है कि मैंने मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी, 10–12 रोज पहले। इस बारे में विचार करने के लिये उनकी एक कमेटी बनाई गई है। इस संदर्भ में उनकी तरफ से जो भी सुझाव आयेंगे, मजदूरों की साझेदारी के मामले में, उनको स्वीकार करने के लिए हम तैयार है।

Non-release of full quota of white printing paper by paper mills

*490. SHRI HARSH DEO MALAVIYA:†
DR. V. P. DUTT:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the paper mills are not releasing full quota of white printing paper;

(b) whether it is also a fact that the Federation of the Indian Publishers is reported to have warned that unless the paper mills cooperated and released immediately the full quota of white printing paper they needed, text books for the coming academic year would either be priced very high or would not be available, and

(c) if so, what steps Government have taken to ensure adequate supply of paper by the mills to the publishers?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Harsh Deo Malaviya.